designed and the sites for such stations have been identified. It is found that such stations located at a (distance from the coal-fields will be competitive with thw diesel power and comparable with cost from coal based power even at present cost and will become even more competitive with volume production and technology developments.

(c) Yes, Sir. The Government have been installing small scale solar systems for electricity generation for street, community and domestic lighting community T. V. drinking water pumping, etc., under its demonstration and field evaluation programmes.

(d) Details are given in the Annexure- */See* Apoendix CLI, Annexure .No. 51 J.

सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी का राष्ट्रीयकरण

621. **श्री० इक्तरार अहमद खान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सवाई माधोपुर स्थित एक सीमेंट फैक्टरी पिछले 2 वर्षों से बन्द पड़ी है और इसके 25 हजार कर्मकार जो बेरोजगार हो गए हैं भूखे मर रहे हैं, यदि हां, तो इस मुद्दे को न सुलझाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस फैक्टरी के बंद होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :

(क) मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड एक सीमेंट संयंत्र सवाई माधोपुर में हैं, जिसमें 3500 कर्मचारी काम कर रहे हैं न कि 25,000। इसे राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी संबंधी सुविधाएं दी गई थी तथापि, गारंटी का नवीकरण न किए जाने के कारण 1-7-1988 से बैंक कार्य बन्द है। राज्य सरकार और कंपनी के अनुरोध पर औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को पुनर्स्थापना योजना तैयार करने के लिये एक संचालक अभिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। मामले की सभी सम्बद्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात बोर्ड की विशेष न्याय पीठ अपनी 30 जनवरी, 1989 को हुई सुनवाई में प्रथमत: इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन जीव्य नहीं बनाया जा सकता और यह न्यायसंगत तथा उचित है कि इसें बन्द कर दिया जाए। 5-4-89 को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करते हुए तदनुसार सभी सम्बद्ध पक्षों से सुझाव टिप्पणियां / आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया था।

इस बीच, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा एकक को बन्द करने के बारे में 30 जनवरी, 1989 को पारित आदेश को एकक के प्रवर्तकों में से एक ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण के अपील प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। अपील प्राधिकरण ने अपने दिनांक 12-6-89 के आदेश द्वारा उसके द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में जांच करने के लिए इसे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लौट दिया है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अन्तिम विचार प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) रुग्ण और अजीव्य संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण करना सरकार की नीति नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड गैर-सरकारी क्षेत्र में है।